Q1. भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभावों का समालोचनात्मक वर्णन कीजिए। [8 अंक]

Q1. Critically describe the effects of globalisation on the Indian economy. [8 Marks]

वैश्वीकरण से तात्पर्य सम्पूर्ण विश्व के सामाजिक-आर्थिक जुड़ाव से है। इसमें सभी देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं।

वैश्वीकरण के प्रभाव :-

सकारात्मक	नकारात्मक
1. आर्थिक विकास दर में वृद्धि। 1991 से पूर्व → लगभग 4% वर्तमान में - 6-7%	1. आर्थिक असमानता में वृद्धि। ऑक्सफेम → ऊपरी 1% लोगों के पास 70% संपत्ति
2. निर्यात में वृद्धि → भारत कृषि निर्यात में Top-10 में।	2. व्यापार घाटा में वृद्धि चीन के साथ 100 बि. डॉलर का व्यापार घाटा।

©MakeIAS www.makeias.in 9899282107, 8700476287 Delhi Prayagraj Lucknow

(iii) 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था।	(iii) द्वितीयक क्षेत्रक का सीमित विकास। GDP में – 29% हिस्सेदारी
(iv) प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार – 1,97000	(v) बेरोजगारी में वृद्धि। तथा श्रम कानून को नज़र अंदाज किया गया।

निष्कर्ष: वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रभाव है। 2047 तक विकसित देश बनने तथा 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के लिए सकारात्मक प्रयासों पर जोर देने की आवश्यकता है।

Q2. भारत में बेरोजगारी की दर को कम करने हेतु कौन-से नवाचारी रोजगारों के सृजन की आवश्यकता है ? चर्चा कीजिए। [8 अंक]

Q2. Which innovative jobs need to be created to reduce the unemployment rate in India? Discuss. [8 Marks]

बेरोजगारी → ILO के अनुसार -
"ऐसी स्थिति जब व्यक्ति द्वारा सार्थक प्रयास करने के बावजूद भी क्षमता अनुसार रोजगार नहीं मिलता है"

CMIE के अनुसार → बेरोजगारी दर
7.1%

→ बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रयास :-

क्योंकि :-
- (i) अधिक जनसंख्या सभी को रोजगार प्रदान करने के लिए।
- (ii) अकुशल श्रम की अधिकता
  इंडिया स्किल रिपोर्ट → 47% स्नातक रोजगार योग्य।
- (iii) प्रच्छन्न बेरोजगारी

MAKE IAS
Make Advanced Knowledge Easy

(iv) द्वितीयक क्षेत्रक का कम विकास।
↳ भारत में GDP का सिर्फ 29%
जब कि विकसित देशों में GDP में 50% से अधिक का योगदान।

सरकार के प्रयास :

- स्वरोजगार को प्रोत्साहन
  - ↳ स्वनिधि योजना
  - ↳ स्टैण्ड अप योजना
- कौशल युक्त श्रम हेतु
  - ↳ कौशल विकास योजना
- ↳ MSME क्षेत्र को बढ़ावा
  - ↳ ODOP

निष्कर्ष: सरकार को बेरोजगारी दूर करने के लिए उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने, कौशल युक्त बनाना आवश्यक है।

Q3. सरकारी बजट के घटकों का वर्णन कीजिए। अर्थव्यवस्था पर बजट के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। [8 अंक]

Q3. Describe the components of the government budget. Explain the effects of the budget on the economy. [8 Marks]

सरकारी बजट: सरकार के एक वित्तीय वर्ष के कुल आय-व्यय का विवरण होता है। जिसे संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत 'वार्षिक वित्तीय विवरण' के नाम से प्रस्तुत किया जाता है।

घटक

- आय / प्राप्तियाँ
  - राजस्व प्राप्ति ⇓ कर, ऋण आदि से प्राप्त होने वाला धन।
  - पूंजीगत प्राप्ति ⇓ पूंजीगत निर्माण से लाभ।
- व्यय
  - राजस्व व्यय ⇓ सेलरी, पेंशन कल्याणकारी योजनाओं में खर्च
  - पूंजीगत व्यय ⇓ अवसंरचना विकास हेतु व्यय

अर्थव्यवस्था पर बजट के प्रभाव :-

- पूंजीगत व्यय सरकार की संपत्तियों में बढ़ोत्तरी करता है।

- राजस्व व्यय → बाजार में मांग को बढ़ाता है → उत्पादन बढ़ाता है।

→ राजस्व प्राप्ति → लोककल्याणकारी योजनाओं में व्यय को बढ़ाता है जिससे गरीबी, बेरोजगारी, समावेशी विकास में सहायता।

→ पूंजीगत प्राप्तियाँ :- सरकार के पूर्व निवेश का लाभांश। होती हैं। जो व्यापार-वाणिज्य में बढ़ोत्तरी में सहायक है।

निष्कर्षत: प्रत्येक वर्ष बजट पेश किया जाता है तथा आर्थिक समीक्षा के माध्यम से पिछले खर्च का विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

Q4. ग्रीन हाइड्रोजन के लाभ और अनुप्रयोगों को स्पष्ट कीजिये। [8 अंक]

Q4. Explain the benefits and applications of green hydrogen. [8 Marks]

ग्रीन हाइड्रोजन :- हाइड्रोजन उत्पादन की प्रक्रिया में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग करने से है। जैसे-
इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा हाइड्रोजन उत्पादन

लाभ :-

- (i) SDG-7 → स्वच्छ एवं वहनीय ऊर्जा प्राप्त करने में।
- (ii) डिकार्बनाइजेशन में महत्वपूर्ण
- (iii) 2070 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन में।
- (iv) नीति आयोग → इलेक्ट्रिक वाहन से ऊर्जा माँग में 64% की वृद्धि होगी → पूरा करने में।
- (v) जलवायु परिवर्तन को रोकने में।

©MakeIAS www.makeias.in 9899282107, 8700476287 Delhi Prayagraj Lucknow

अनुप्रयोग → हाइड्रोजन ईंधन चालित परिवहन
जैसे- हाल ही में लद्दाख में हाइड्रोजन संचालित बस।

→ जर्मनी में प्रथम हाइड्रोजन संचालित ट्रेन।

→ विद्युत उत्पादन में।

→ दैनिक उपयोग में → खाना बनाने में, प्रेस करने में।

→ भविष्य में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी सहयोगी।

निष्कर्ष: ग्रीन हाइड्रोजन स्वच्छ एवं वहनीय ऊर्जा के एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है परन्तु तकनीकी समस्या, उच्च लागत, वित्त की समस्या जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं। जिन्हें PPP, R&D में विकास व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से हल किया जा सकता है।

©MakeIAS www.makeias.in 9899282107, 8700476287 Delhi Prayagraj Lucknow

Q5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्यों का वर्णन करते हुए, इसके क्रियान्वयन में आने वाली विभिन्न समस्याओं की विवेचना कीजिए। [8 अंक]

Q5. Describing the objectives of the Public Distribution System, discuss the various problems faced in its implementation. [8 Marks]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से तात्पर्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु लक्षित लाभार्थी को अनाज की सहज एवं वहनीय पहुँच सुनिश्चित करना है।

+ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 75% तथा शहरी गरीबों तक 50% पहुँच।

उद्देश्य :
- खाद्य सुरक्षा
- गरीबी कम करना
- कल्याणकारी राज्य की अवधारणा
- शिक्षा में बढ़ोत्तरी
  - मिड-डे मील

समस्याएं

- **भ्रष्टाचार**
  - योजना आयोग- 36% लीकेज
- **लक्षित लाभार्थी तक पहुँच नहीं।**
  - NSSO- 2009 में 61% बहिष्करण एवं 24% समावेशन त्रुटियाँ
- **गुणवत्ता**
  - भण्डारण की कमी के कारण सड़ा हुआ अनाज।
- **घटतौली**
  - कोटा डीलर द्वारा कम तौलना।
- **अपर्याप्त मात्रा**
  - 5kg/यूनिट प्रति महीने के लिए

निष्कर्ष: PDS में समस्याएं विद्यमान हैं लेकिन JAM ट्रिनिटी, ई-गवर्नेंस व GPS के माध्यम से हल की जा सकती हैं। सरकार 'वन नेशन वन कार्ड' के माध्यम से प्रयासरत है।

Q6. उर्ध्व व अधोप्रवाह आवश्यकताएँ क्या होती हैं ? खाद्य प्रसंस्करण में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। [8 अंक]

Q6. What are upstream and downstream requirements? Describe its importance in food processing. [8 Marks]

उर्ध्व प्रवाह आवश्यकताएँ :- किसी उद्योग की स्थापना हेतु कच्चे माल की उपलब्धता, अवसंरचना विकास उर्ध्व प्रवाह आवश्यकताएँ हैं, जबकि बाजार की उपलब्धता, उत्पादन का संचलन हेतु परिवहन सुविधा और अधो प्रवाह हैं।

उर्ध्व प्रवाह ⟷ अधो प्रवाह

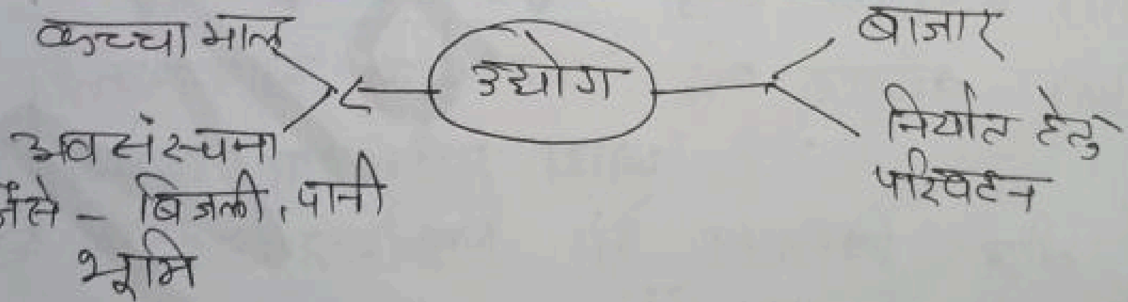

→ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में महत्व :- यह भारत में 'सनराइज उद्योग' है जिसका GVA में 1.69% का योगदान है

पर्याप्त आपूर्ति श्रृंखला के विकास से सर्वाधिक रोजगार व निर्यात की क्षमता ~~की~~ ~~योग्य~~ रखता है।

उर्ध्व प्रवाह व अधो प्रवाह :-

(i) कच्चे माल की तीव्र एवं सुचारु उपलब्धता

(ii) परिवहन व बिजली की सुविधा → कच्चे माल को प्रसंस्कृत करने के लिए

↑

उद्योग

↓

(iii) भण्डारण हेतु कोल्ड स्टोरेज

(iv) बाजार की उपलब्धता आवश्यक है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के तीव्र विकास में विकसित आपूर्ति श्रृंखला अति आवश्यक है

निष्कर्षतः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की क्षमता उपलब्ध है जिसे कैश करने की आवश्यकता है जिसमें PPP मॉडल सहयोगी होगा।

Q7. भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् भूमि सुधार के विकास क्रम को समझाते हुए, इसके प्रभावों की चर्चा कीजिए। [8 अंक]

Q7. Explaining the course of development of land reforms in India after independence, discuss its effects. [8 Marks]

भूमि सुधार से तात्पर्य सभी वर्गों में भूमि संसाधन के पुनर्वितरण से है।

→ भूमि सुधार :-

स्वतंत्रता पूर्व :-
- → राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन
- → ग्रामदान आन्दोलन
- → भूदान आंदोलन

स्वतंत्रता पश्चात्

- जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, लगान नियंत्रण आदि।
- चकबंदी, हदबंदी, सहकारी कृषि

©MakeIAS www.makeias.in 9899282107, 8700476287 Delhi Prayagraj Lucknow

MAKE IAS
Make Advanced Knowledge Easy

प्रभाव

- भूमि का पुनर्वितरण → भूमिहीनों को भूमि प्राप्त।
- जमींदारी प्रथा उन्मूलन।
- ~~दास~~ बंधुआ मजदूरी उन्मूलन।
- जोतों का एकत्रीकरण
- → भूमि का विकेन्द्रीकरण

सीमा → कुछ राज्यों तक सीमित बंगाल, केरल।

→ परिवार के अन्य सदस्यों के नाम जमीन।

→ दस्तावेजों की अनुपलब्धता

निष्कर्षत: भूमि के पुनर्वितरण में सीमित सफलता प्राप्त हुई। लेकिन सरकार चकबंदी, लगान नियंत्रण के माध्यम से प्रयासरत है।

Q8. भारत में समावेशी विकास को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। साथ ही इसके समाधान सुझाइए। [8 अंक]

Q8. Explain the challenges faced in achieving inclusive growth in India. Also suggest its solution. [8 Marks]

समावेशी विकास से तात्पर्य समाज के सभी वर्गों तक लाभ पहुँचाने से है।
यह वितरणात्मक लाभ की अवधारणा है।

चुनौतियाँ :-

(i) व्यापक असमानता :-

क्षेत्रीय	वर्गीय
जैसे- प॰ यूपी अधिक विकसित तथा बुंदेलखण्ड निम्न।	महिलाओं की कम भागीदारी। PLFS-2022 कार्यबल में-16%.

(ii) अशिक्षा → 73% साक्षरता

(iii) अकुशल कार्यबल

- (iv) भ्रष्टाचार
- (v) राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव।
- (vi) सामाजिक रूढ़ियाँ

समाधान :-

- (i) DBT के माध्यम से आर्थिक सहायता।
- (ii) कौशल विकास एवं रोजगार की उपलब्धता।
- स्वरोजगार की उपलब्धता
  - स्वनिधि योजना
  - मनरेगा।

निष्कर्षत: संवैधानिक आदर्शों को पूरा करने तथा लोक-कल्याणकारी राज्य व सुशासन की अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए समावेशी विकास आवश्यक है।

Q9. हरित परिवहन क्या होते हैं ? वर्तमान समय में इनकी आवश्यकता को चिह्नित कीजिए। [8 अंक]

Q9. What is green transport? Outline their needs in the present time. [8 Marks]

हरित परिवहन से तात्पर्य ऐसी परिवहन सुविधा से जो हरित ऊर्जा (नवीकरणीय ऊर्जा) से संचालित होती है। जैसे- लद्दाख में हाइड्रोजन संचालित बस।

E100 → परिवहन।

→ वर्तमान में आवश्यकता :-

- (i) भारत का कुल 3 कार्बन उत्सर्जन का 1/3 जैव ऊर्जा पर आधारित परिवहन द्वारा।
- (ii) कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए।
- (iii) रसद लागत कम करने के लिए। वर्तमान में- 14%
  लक्ष्य - 8%.

©MakeIAS www.makeias.in 9899282107, 8700476287 Delhi Prayagraj Lucknow

—(iv) जलवायु परिवर्तन की रोकथाम हेतु

—(v) पंचामृत (2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन) प्राप्त करने के लिए।

→(vi) SDG-7 प्राप्त करने के लिए।

प्रयास → राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018
2025 तक E20

→ हाइड्रोजन नीति → 2030 तक 5 बि० टन हाइड्रोजन उत्पादन

→ इलेक्ट्रिक वाहन नीति

→ फेम इंडिया योजना, ई-बस

निष्कर्ष: लाइफ मिशन एवं आर्थिक बचत हेतु हरित परिवहन को अपनाने की आवश्यकता है।

Q10. राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व का वर्णन कीजिए। [8 अंक]

Q10. Describe the importance of science and technology in national security. [8 Marks]

राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान व प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिसे निम्न प्रकार से देखा जा सकता है—

युद्ध के समय	शांति के समय
(i) आधुनिक हथियारों की उपलब्धता। जैसे- लड़ाकू विमान, आधुनिक मिसाइल	(i) सीमाओं की रखवाली के लिए जैसे- थर्मल स्कैनिंग, CCTV कैमरा।
(ii) सुरक्षा हेतु आधुनिक उपकरण (जैसे- एयर डिफेंस सिस्टम	(ii) आत्मनिर्भर बनाने के लिए औद्योगिक उत्पादन करना।
(iii) क्षेत्रीय नेवीगेशन सिस्टम से दुश्मन की जानकारी	(iii) संचार प्रौद्योगिकी के विकास से त्वरित सूचना आदान प्रदान

IRNSS भारतीय उपमहाद्वीपीय की जानकारी उपलब्ध करायेगा।	(iv) सैटेलाइट से मौसम की जानकारी। (v) शिक्षा एवं कौशल विकास में

निष्कर्षतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा युद्ध और युद्ध पूर्व व पश्चात् राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस जैसे देश इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।

Q11. भारत कृषि उत्पादन का भंडारण, ढुलाई एवं विपणन के समक्ष विभिन्न चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इन चुनौतियों से निपटने हेतु उपाय सुझाइए। [12 अंक]

Q11. Various challenges exist before the storage, transportation and marketing of India's agricultural produce. Suggest ways to deal with these challenges. [12 Marks]

भारत कृषि प्रधान देश है जिसकी 47% जनसंख्या (Eco. Survey 2022-23) कृषि कार्यों में संलग्न है।

परन्तु भण्डारण, ढुलाई एवं विपणन संबंधी समस्याएँ विद्यमान हैं—

भण्डारण संबंधी

- FCI के पास सिर्फ 47% उत्पादित अनाज भण्डारण की सुविधा।
- सहकारी गोदामों का अभाव।
- किसानों के पास सीमित संसाधन।
- कोल्ड स्टोरेज का अभाव।

उपाय

- सहकारी क्षेत्र में भण्डारण सुविधा का विकास जैसे- सहकारी भण्डारण योजना

→ PPP के आधार पर भण्डारण सुविधा।
  → गोदाम
  → कोल्ड स्टोरेज
→ सहकारी कृषि एवं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रोत्साहन।

ढुलाई संबंधी चुनौती

→ उच्च रसद लागत → आर्थिक सर्वे - 2022-23
  → उत्पादन लागत का 14-15% जो विकसित देशों में 8%.

→ सड़क परिवहन पर आश्रित → 70% से अधिक माल ढुलाई सड़क से। लागत अधिक।

→ परंपरागत रूप से ढुलाई → अनाज की बर्बादी

उपाय → केंद्र सरकार नई रसद नीति।
  → खाद्य पार्कों का विकास
  → अवसंरचना विकास कोष।

©MakeIAS www.makeias.in 9899282107, 8700476287 Delhi Prayagraj Lucknow

→ लॉजिस्टिक क्षेत्र में नई तकनीकों का प्रयोग।

विपणन संबंधी चुनौती → MSP पर सीमित खरीद।

→ APMC मंडियों में बेचने की बाध्यता।

→ बिचौलियों का कार्टेल

→ मंडियों विविध कर एवं शुल्क

→ उपज को बाजार बेचने पर कानूनी दण्ड।

उपाय → E-NAM को प्रोत्साहन

→ MSP पर खरीद नियमों एवं अवसंरचना में बदलाव।

→ APMC की मंडियों में बेचने की बाध्यता को समाप्त।

निष्कर्षत: भण्डारण, ढुलाई और विपणन संबंधी चुनौतियों को दूर करके ही कृषकों की आय में बढ़ोतरी तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है

©MakeIAS www.makeias.in 9899282107, 8700476287 Delhi Prayagraj Lucknow

Q12. "यद्यपि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का कई गुना विस्तार किया है, तथापि मानव विकास के मामले में उसने अधिक प्रगति नहीं की है।" हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2022 के संदर्भ में उक्त कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। [12 अंक]

Q12. "Although India has expanded its economy manifold, it has not made much progress in terms of human development." Critically analyze the above statement with reference to the recently released Human Development Index 2022. [12 Marks]

हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 135वीं थी। जो मानव विकास की निम्न स्थिति को प्रदर्शित करती है।

→ अर्थव्यवस्था का कई गुना विस्तार :-

- (i) वर्तमान में भारत की GDP 3.2 ट्रिलियन डॉलर की।
- विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था।
- प्रति व्यक्ति आय 1,97000।
- सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था।

©MakeIAS www.makeias.in 9899282107, 8700476287 Delhi Prayagraj Lucknow
©MakeIAS

→ मानव विकास की निम्न प्रगति :

- (i) MPI-2022 के अनुसार 22.8 करोड़ जनसंख्या गरीब। विश्व में सर्वाधिक।
- (ii) सर्वाधिक आर्थिक असमानता वाला देश (विश्व बैंक)
- (iii) 56% महिलाएँ एनीमिया से पीड़ित।
- (iv) 37% जनसंख्या निरक्षर (जनगणना-2011)
- (v) ~~ह्~~ कुपोषण → हर तीसरा बच्चा नाटा तथा हर 5वाँ बच्चा ~~विकास~~ कमजोर।

→ मानव विकास के प्रयास

- मनरेगा (रोजगार की उपलब्धता)
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधि० - 2013
  PDS

©MakeIAS www.makeias.in 9899282107, 8700476287 Delhi Prayagraj Lucknow

- मिड डे मील योजना
- RTE – 2009 → शिक्षा का अधिकार
→ महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन
→ कौशल विकास मिशन

निष्कर्षतः भारत सरकार मानव विकास प्रयासरत है। जिसमें गरीबी का दुष्चक्र, निम्न अवसंरचना विकास, अशिक्षा ~~आ~~ मुख्य चुनौती है।

Q13. संगठित अपराध को परिभाषित कीजिए, यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार की चुनौती उत्पन्न करते हैं, साथ ही बताइए कि भारत सरकार द्वारा इनसे निपटने हेतु कौन से कदम उठाए गए हैं? [12 अंक]

Q13. Define Organized Crime? What kind of challenge do they present for India's internal security? Also, what steps have been taken by the Government of India to address them? [12 Marks]

संगठित अपराध : से तात्पर्य तीन या उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा सुनियोजित ढंग से किसी अपराध को अंजाम देने से है।

जैसे- मानव तस्करी, ड्रग तस्करी

भारतीय आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती :—

- (i) आतंकवाद → पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद कश्मीर व अन्य हिस्सों में चुनौती बने हुए हैं।
- (ii) ड्रग तस्करी :- गोल्डन ट्राइंगल तथा गोल्डन क्रीसेंट से निकटता के कारण सुभेद्यता।

(iii) मानव तस्करी :- नेपाल, बांग्लादेश भूटान से बाल तस्करी एवं महिलाओं की तस्करी की जाती है जो वेश्यावृत्ति, अंग व्यापार एवं दास के रूप में रखे जाते हैं

(iv) ~~धन~~ धन शोधन :-
↳ गैर-कानूनी तरीकों से अर्जित आय को कानून वैधता का प्रयास करना।

निपटने के उपाय

- धन शोधन नियंत्रण अधि० - 2002
- ~~PCPA~~ स्वापक नियंत्रण अधि०
- सीमाओं पर CCTV, थर्मल इमेजिंग के माध्यम से निगरानी
- आतंकवाद की रोकथाम हेतु

NIA का गठन, TADA, POTA जैसे कानून।

→ ED, CBI जैसी एजेंसियों का अधिदेश।

आगे की राह:

→ (i) NIA, ED, CBI जैसी एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापन।

→ तकनीकी का प्रयोग करना।

निष्कर्षत: संगठित अपराध भारतीय आँतरिक सुरक्षा के साथ-साथ संपूर्ण विश्व की शांति के लिए खतरा है। जिसकी रोकथाम की आवश्यकता है।

©MakeIAS www.makeias.in 9899282107, 8700476287 Delhi Prayagraj Lucknow

Q14. हाल ही में विश्व आर्थिक मंच (WEF) के द्वारा प्रकाशित वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2022 के अनुसार AI कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 22% है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जाने चाहिए? [12 अंक]

Q14. According to the recent Global Gender Gap Report, 2022 published by the World Economic Forum (WEF), the share of woman in the AI workforce is only 22%. What efforts should be made by the government to encourage this? [12 Marks]

वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022, के अनुसार AI में महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 22% है जो निम्न स्थिति में है।

→ महिलाओं की तकनीकी भागीदारी में कमी के कारण :-

- (i) STEM विषयों में महिलाओं की कम रूचि।
- (ii) रूढ़िगत सोच → जैसे - लड़कियों को गणित नहीं आता
- (iii) विज्ञान विषयों की पढ़ाई का खर्च अधिक → गरीबी और लैंगिक भेदभाव

- पढ़ाई हेतु घर से बाहर न भेजना। पारिवारिक ज़िम्मेदारी
- बाल विवाह। कम उम्र में विवाह। <u>विश्व बैंक</u> के अनुसार पूरी दुनिया के 50% बाल विवाह भारत में।

→ **भागीदारी हेतु सरकार के प्रयास**

- <u>किरन योजना</u> :- शोध कार्यों में महिलाओं को बढ़ावा हेतु।
- विवाह की उम्र बढ़ाना।
- <u>स्पेस 4 वीमेन</u> → UN की पहल को लागू करना।
- विज्ञान विषयों में नामांकन बढ़ाने हेतु महिला वैज्ञानिकों के बारे में अध्ययन करवाना
- STEM विषयों में अध्यापकों की संख्या बढ़ाना।

↳ ~~End~~ INDIAai पहल ।

निष्कर्ष: सरकार को समावेशी समाज बनाने के लिए ~~बिस~~ विज्ञान-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाओं की पहुँच बढ़ानी होगी ।

Q15. बढ़ते शहरीकरण तथा औद्योगीकरण से ऊर्जा मांग में भी वृद्धि होगी। इस हेतु भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने होंगे? [12 अंक]

Q15. Increasing urbanization and industrialization will also increase energy demand. For this, what steps will have to be taken by India to ensure its energy security? [12 Marks]

एक रिपोर्ट के अनुसार, 2050 तक भारत की 50% से अधिक आबादी शहरों में निवास करेगी। तथा 2047 तक विकसित राष्ट्र का लक्ष्य भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को दर्शाता है।

विश्व बैंक के अनुसार - भारत की ऊर्जा मांग में प्रति वर्ष 3% की वृद्धि हो रही है। जो 2030 तक भारत को तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश बना देगी।

→ शहरीकरण एवं औद्योगिकरण से ऊर्जा मांग में वृद्धि :

- जीवन स्तर में बढ़ोत्तरी प्रति व्यक्ति ऊर्जा मांग में बढ़ोत्तरी।

©MakeIAS www.makeias.in 9899282107, 8700476287 Delhi Prayagraj Lucknow

1:29
1:43

→ औद्योगिक उत्पादन हेतु ऊर्जा की माँग

→ इलेक्ट्रिक वाहन से 64% ऊर्जा माँग में वृद्धि (नीति आयोग)

सरकार के प्रयास

- (i) नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। जैसे- 2030 तक 500 GW उत्पादन का लक्ष्य।
- (ii) 2045 तक कुल ऊर्जा माँग का 50% नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य।
- (iii) इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहन। जैसे- फेम इंडिया योजना
  - ↳ ई-बस योजना
- (iv) लाइफ मिशन → पर्यावरण अनुकूल

ऊर्जा उत्पादन

→ राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन

→ स्मार्ट मीटर एवं प्रीपेड मीटर

निष्कर्षतः शहरीकरण के बढ़ने के साथ अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार जैव ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए प्रयासरत है।

Q16. वित्तीय समावेशन हेतु सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'जन धन योजना' ने 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस सन्दर्भ में योजना की उपलब्धियों का मूल्याङ्कन कीजिये। [12 अंक]

Q16. Government's ambitious scheme for financial inclusion 'Jan Dhan Yojana' has completed 8 years. In this context, evaluate the achievements of the scheme. [12 Marks]

जन धन योजना, अगस्त 2015 में शुरू की गई केन्द्र सरकार की योजना थी।

जिसके अंतर्गत BSBDA (बेसिक सेविंग एवं बैंक डिपोजिट अकाउंट), रुपे कार्ड के साथ खाता खोला गया।

उद्देश्य :-

→ वित्तीय समावेशन करना

→ सुदूर क्षेत्रों में जनजाति, महिलाओं तक बैंक की पहुँच।

→ भ्रष्टाचार को खत्म करना।

MAKE IAS
Make Advanced Knowledge Easy

योजना की उपलब्धियाँ

- (i) 70% जनसंख्या की बैंकों तक पहुँच सुनिश्चित हुई।
- (ii) पहल (सबसे बड़ी DBT) योजना का कार्यान्वयन जनधन योजना के कारण संभव।
- (iii) कोरोना के समय महिलाओं प्रत्यक्ष सहायता। 500 रुपये की तीन किस्तें।
- (iv) जननी सुरक्षा योजना, मातृ सुरक्षा योजना का लाभ DBT के माध्यम से।
- (v) बिचौलियों को कम करने में सहायता।
- (vi) ~~सरकार~~ किसान सम्मान निधि, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण।

©MakeIAS www.makeias.in 9899282107, 8700476287 Delhi Prayagraj Lucknow

चुनौती
- (i) 10 करोड़ से अधिक निष्क्रिय खाते।
- (ii) बैंकों का सुदूर स्थित होना।
- (iii) बचत कम होना।

निष्कर्षतः जनधन योजना ने वित्तीय समावेशन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिसे वित्तीय साक्षरता, बैंक मित्र आदि के माध्यम और अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है

Q17. भारत सरकार रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिये विभिन्न पहलों का संचालन कर रही है, इसके बावजूद इसकी गति काफी मंद है। चर्चा कीजिये। [12 अंक]

Q17. The Government of India is undertaking various initiatives for the modernization of the defence sector, yet its pace is very slow. Have a discussion. [12 Marks]

~~भारत~~

रक्षा क्षेत्र आधुनिकीकरण से तात्पर्य रक्षा क्षेत्र में नई तकनीकों के उपयोग से है जैसे- AI का उपयोग, क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग।

आवश्यकता

- (i) रक्षा आयात को कम करना।
  सिप्री के अनुसार→ भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक।
- (ii) चीन जैसे तकनीकी युक्त देश का सामना करने के लिए।
- (iii) वैश्विक लीडर के रूप में उभरने के लिए।
- (iv) रक्षा निर्यात से आय के विविधी-

©MakeIAS www.makeias.in 9899282107, 8700476287 Delhi Prayagraj Lucknow

करण के लिए।

भारत सरकार की पहलें :-

- (i) रक्षा क्षेत्र में 74% तक ऑटोमेटेड रूट से FDI की स्वीकृत।
- (ii) PPP के आधार पर रक्षा क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा।
- (iii) रक्षा औद्योगिक गलियारों का विकास।

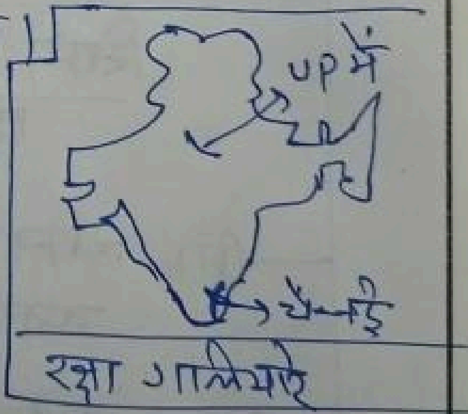

- (iv) "रक्षा स्वदेशीकरण योजना" — 2011
- (v) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना जैसे- रूस के साथ AK-209 का विकास

* फ्रांस से P-75 स्कॉर्पीन पनडुब्बी का तकनीकी हस्तांतरण
* अमेरिका के साथ फाइटर जेट विमान के इंजन के विकास हेतु समझौता।

मंदगति के कारण :-

- (i) समझौतों के क्रियान्वयन में देरी।
- (ii) R&D पर कम खर्च। GDP का मात्र 0.6%
- (iii) विनियमक ढांचे की कमी के कारण निजी निवेशकों की कमी।
- (iv) बौद्धिक संपदा चोरी का डर।
- (v) वित्त की कमी → बजट का अधिकांश भाग रक्षा आयात और वेतन व पेंशन पर खर्च।

निष्कर्षत: सरकार रक्षा आधुनिकीकरण के लिए प्रयासरत है जिसे PPP के तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जल्दी प्राप्त किया जा सकता है

MAKE IAS
Make Advanced Knowledge Easy

Q18. भारत ने अपने क्षेत्र की भू-सामरिक अस्थिरता और साइबर खतरे के बारे में जागरूकता के बावजूद साइबर स्पेस सुरक्षा के लिए अपनी नीति और सिद्धांत विकसित करने में केवल अत्यधिक मंद प्रगति की है। चर्चा कीजिये। [12 अंक]

Q18. India has made only very slow progress in developing its policy and principles for cyberspace security, despite the geo-strategic instability of its region and its awareness of cyber threats. Have a discussion. [12 Marks]

साइबर खतरे :- तात्पर्य साइबर स्पेस में उपलब्ध सूचना के अनाधिकृत प्रयोग की सुभेद्यता से है।

→ साइबर खतरे और भू-सामरिक अस्थिरता में संबंध :-

(i) साइबर हमले से क्रिटिकल अवसंरचना पर हमला। → संपूर्ण व्यवस्था पर खतरा
जैसे - AIIMS दिल्ली की वेबसाइट हैक तथा संपूर्ण नेटवर्क हैक,

(ii) परमाणु संपन्न देश → परमाणु युद्ध का खतरा।

(iii) वित्तीय अस्थिरता का खतरा।

©MakeIAS www.makeias.in 9899282107, 8700476287 Delhi Prayagraj Lucknow

→ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की प्रगति :

- (i) राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 का विकास।
- (ii) IT Act 2000 तथा 2008 में संशोधन।
- (iii) राष्ट्रीय डिजिटल सुरक्षा नीति 2018
- (iv) CERT-In का विकास
- (v) क्रिटिकल अवसंरचना के विकास हेतु NCIIPC

मंद प्रगति के कारण :-

- (i) आधुनिक तकनीकी का विकास नहीं। जैसे- क्वांटम कम्प्यूटर, उच्च क्षमता वाले सुपर कम्प्यूटर

(ii) वित्त का अभाव :- बजट का अधिकांश भाग कल्याणकारी योजना एवं वेतन-पेंशन पर

(iii) राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव एवं डिजिटल साक्षरता का अभाव।

~~(iv) तकनीकी~~

निष्कर्षत: भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा हेतु स्पष्ट नीति का निर्माण में देरी की है लेकिन चीन जैसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए डिजिटल अवसंरचना विकास एवं सुरक्षा नीति आवश्यक है

Q19. भारत में 5G तकनीकी की संभावना और संबंधित मुद्दों को उजागर कीजिये। साथ ही इन मुद्दों के समाधान सुझाइए। [12 अंक]

Q19. Highlight the potential and related issues of 5G technology in India. Also suggest solutions to these issues. [12 Marks]

5G तकनीकी डाटा सँचरण की गति के आधार पर 5वीं पीढ़ी की तकनीकी है जो 4G का उन्नत संस्करण है।

भारत में संभावना :-

- (i) एक विस्तृत बाजार की उपलब्धता।
- (ii) तकनीकी के विकास के मामले में उभरता क्षेत्र।
- (iii) फाइबर ग्रिड के माध्यम से उच्च डेटा सँचरण की गति। जिसमें अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की उच्च दर।
- (iv) भारत के तकनीकी विकास के लिए महत्वपूर्ण है

MAKE IAS
Make Advanced Knowledge Easy

संबंधित मुद्दे

- **निम्न अवसंरचना विकास एवं पहुँच**: NSSO के अनुसार 27% परिवारों के पास इंटरनेट की पहुँच तथा 12.5% छात्रों को उपलब्धता।
- **लैंगिक असमानता**:- 16% महिलाओं की इंटरनेट तक पहुँच।
- **क्षेत्रीय असमानता**:-
  - पहाड़ी एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं।
- **गरीबी**:- MPI-2021 के अनुसार 22.8 करोड़ गरीब।
- साइबर अपराध

©MakeIAS www.makeias.in 9899282107, 8700476287 Delhi Prayagraj Lucknow

समाधान

- विद्यालय, कॉलेज में डिजिटल साक्षरता
- सार्वजनिक स्थानों पर फ्री wi-fi
- भारतनेट परियोजना 2.5 लाख गाँव तक पहुँच।
- PM वाणी योजना

निष्कर्षतः समाज के समावेशी विकास हेतु इंटरनेट तक पहुँच आवश्यक है जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकार भी है।

Q20. कार्बन फुटप्रिंट क्या है? कार्बन उत्सर्जन के प्रभावों का वर्णन कीजिए, साथ ही इसके न्यूनीकरण हेतु उपाय सुझाइए। [12 अंक]

Q20. What is the carbon footprint? Describe the effects of carbon emissions, as well as suggest ways to mitigate it. [12 Marks]

कार्बन फुट प्रिंट :- पर्यावरण में कार्बन को अवशोषित करने वाले प्राकृतिक संसाधनों से है। वन क्षेत्रों के अत्यधिक विकास कार्बन फुट-प्रिंट को बढ़ाया जा सकता है।

→ कार्बन उत्सर्जन के प्रभाव :-

- भूमण्डलीय तापन :-
  ~~202~~ 2100 तक 2.1°C तापमान में वृद्धि।

- जलवायु परिवर्तन :-
  कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि से वर्षा की मात्रा एवं अवधि में परिवर्तन।
  ↳ 2050 तक वर्षा की मात्रा में

50% तक वृद्धि।

— समुद्र जल स्तर में वृद्धि:
- ग्लेशियर के पिघलने से जल स्तर में वृद्धि।
- द्वीपीय देशों के ~~जल~~ डूबने का डर।

→ अरब सागर में चक्रवात की आवृत्ति में वृद्धि → हाल ही में विपरजॉय।

→ बाढ़-सूखा जैसी चरम स्थितियों की बारंबारता में वृद्धि

→ कृषि उत्पादन में कमी → भुखमरी
SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थता।

न्यूनीकरण के उपाय

— UNEP के अनुसार—
अगर 8 बिलियन लोगों में से 1 बि० लोग पर्यावरण अनुकूल

जीवनचर्या अपनाते हैं तो कार्बन उत्सर्जन में 20% की कमी।

- वृक्षारोपण करना → हाल ही में
  - ↳ UP सरकार द्वारा 22 करोड़
- मिशन लाइफ को अपनाना।
- → स्वच्छ ईंधन को अपनाना।
  - → उज्ज्वला योजना
  - → इलेक्ट्रिक वाहन
- → पेरिस कन्वेंशन के लक्ष्यों को प्राप्त करना
- → पंचामृत को प्राप्त करने का प्रयास करना।

निष्कर्षत: संधारणीय पृथ्वी व विश्व के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता है। भारत सरकार 2070 तक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है।

©MakeIAS www.makeias.in 9899282107, 8700476287 Delhi Prayagraj Lucknow